



वी. चेट्टियार

कार्यकारी संपादक
8898800908

हिन्दी साप्ताहिक

RNI No.: MAHHIN/2023/89178

एकता केसरी

EKTA KESARI

Issue: 2 • Volume: 17 • Hindi Weekly • Mumbai, Friday 23 to 29 May 2025 • Price 5/- • Page 8

2007 के बाद नई आवास नीति को मिली कैबिनेट से मंजूरी, 5 साल में तैयार होंगे 35 लाख घर

मुंबई: मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्ववाली महाराष्ट्र की महायुति सरकार की मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में नई आवास नीति को मंजूरी दी। नई आवास नीति के तहत 5 वर्षों में 35 लाख मकान बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। सामान्य जनता को सामर्थ्य के अनुरूप किफायती आवास उपलब्ध कराना इसका मूल मकसद है। राज्य सरकार इस पर 70 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। इस योजना के लिए 'मेरा घर, मेरे अधिकार', घोषवाक्य



तैयार किया गया है। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि राज्य की नई आवास नीति ने राज्य के सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए किफायती आवास प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त किया है। यह एक क्रांतिकारी नीति है, जो राज्य के शहरी विकास और आवास को एक नया रूप देगी। इस क्षेत्र में बड़े पैमाने पर निवेश से महाराष्ट्र के 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को

काफी मजबूती मिलेगी। सरकार ने नई आवास नीति के तहत विशेष योजना बनाई है। इसमें 2030 तक प्रत्येक नागरिक को पर्यावरण के अनुकूल टिकाऊ एवं सुरक्षित घर उपलब्ध कराने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। यह नीति 'डेटा-आधारित निर्णय लेने, आधुनिक प्रौद्योगिकी के उपयोग, गतिशीलता और पारदर्शिता तथा सामाजिक समावेशन पर जोर देती है। इसमें झुग्गी पुनर्विकास और नई आवास परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। शेष पृष्ठ 2 पर

पार्किंग होने पर ही खरीद पाएंगे कार... मुंबई में लागू हो सकता है कड़ा नियम, महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री का बड़ा ऐलान

मुंबई: अगर सबकुछ ठीक रहा तो देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के साथ राज्य के तमाम बड़े शहरों में कार खरीदना मुश्किल हो जाएगा। महाराष्ट्र सरकार 'नो पार्किंग-नो कार' की पॉलिसी पर काम कर रही है। ऐसा होने से मुंबई समेत दूसरे बड़े शहरों में कार का सपना संजोने वालों को पहले पार्किंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी।



महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने कहा है कि इसका उद्देश्य शहरों में भीड़भाड़ और अवैध पार्किंग पर अंकुश लगाना है मुंबई में कार

खरीदना होगा मुश्किल राज्य के परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने यह घोषणा की है कि जब तक खरीददार संबंधित नगर निकाय में पार्किंग स्थान का प्रमाण पत्र नहीं दे देता, तब तक उसके नाम

पर नए वाहन का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। परिवहन मंत्री ने कहा यह निर्णय मुख्य रूप से मुंबई महानगर क्षेत्र में बढ़ते पार्किंग संकट से निपटने के लिए लिया गया है। राज्य की नई पार्किंग नीति पर हुई एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद यह घोषणा की गई है। बैठक के बाद मंत्री सरनाईक ने कहा हम पार्किंग स्थल बनाने पर विचार कर रहे हैं। विकास नियमों का पालन किया जाना चाहिए और डेवलपर्स को फ्लैटों के साथ पार्किंग की जगह भी देनी चाहिए। शेष पृष्ठ 2 पर

वीडियो विज्ञापन बैन और होर्डिंग का साइज भी फिक्स एक्शन मोड में BMC



मुंबई के घाटकोपर में पिछले साल अवैध होर्डिंग गिरने से 17 लोगों की मौत हो गई थी। जिसके बाद बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने अब पूरे शहर में अधिकृत होर्डिंग्स पर अपनी निगरानी कड़ी कर दी है। खासकर मानसून से पहले सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से ताकि दोबारा शेष पृष्ठ 2 पर

मुंबई मीठी नदी सफाई घोटाले में ED की एंट्री ; 65 करोड़ की हेराफेरी, अब अधिकारियों की खैर नहीं

मुंबई: मीठी नदी सफाई परियोजना में हुए बड़े घोटाले में अब ED की भी एंट्री हो गई है। ED ने मुंबई EOW की जांच के आधार पर ECIR दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। ED की एंट्री के बाद इस घोटाले में शामिल अभियंताओं, मिडलमैन और ठेकेदारों की मुसिबतें और बढ़ने वाली हैं।

वहीं EOW ने मीठी नदी सफाई परियोजना में हुए 65 करोड़ रुपये के घोटाले को लेकर एक और बड़ा खुलासा किया है। जांच में सामने आया है कि टेंडर देने से पहले और उसके बाद, BMC के अभियंताओं ने यह कभी जांचा ही नहीं कि वास्तव में मीठी नदी में कितनी गाद मौजूद थी और उसे हटाने में कितना समय



लगेगा। इन लोगों का आया नाम EOW के सूत्रों के मुताबिक, 2019 से 2025 तक मीठी नदी में गाद की कोई अधिकृत माप ही नहीं की गई। यह जिम्मेदारी BMC के अभियंताओं प्रशांत रामगुडे, गणेश बेंद्रे और तायशेट्टे की थी। लेकिन दावा है कि इन्होंने अपनी ड्यूटी निभाने के बजाय मिडलमैन के तन कदम और जय

जोशी और ठेकेदारों के साथ मिलकर घोटाले को अंजाम दिया। फर्जी तस्वीरों और दस्तावेजों के सहारे, गाद ज्यादा निकाली, दिखाकर BMC से बड़ी रकम वसूली जाती रही। यह सिलसिला तब तक चला जब तक BMC के दक्षता विभाग ने इस पर आपत्ति नहीं जताई। टेंडर शर्तों के अनुसार एक शेष पृष्ठ 2 पर



संपादकीय

भारत की चिंता बढ़ाता बांग्लादेश

मुख्य सलाहकार मोहम्मद यूनुस की अगुआई वाली बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने देश की सबसे बड़ी और पुरानी राजनीतिक पार्टी अवामी लीग पर आतंकवाद-रोधी कानून के तहत प्रतिबंध लगा दिया है। बांग्लादेश की आजादी की लड़ाई का नेतृत्व बंगबंधु शेख मुजीबुर्रहमान ने किया था। उन्होंने भारत के सहयोग से बांग्लादेश को पाकिस्तान से स्वतंत्रता दिलाई और अवामी लीग को एक मजबूत राजनीतिक दल के रूप में स्थापित किया। वर्तमान में अवामी लीग की नेता और बांग्लादेश से निर्वासित पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना इन दिनों भारत में रह रही हैं। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने उनके खिलाफ आतंकवाद-रोधी कानून के तहत सैकड़ों मामले दर्ज किए हैं, जिनमें हत्या, आगजनी और हिंसा जैसे गंभीर आरोप शामिल हैं। यदि अवामी लीग आगामी चुनावों में भाग नहीं ले पाती तो यह बांग्लादेश के लोकतांत्रिक ढांचे और भारत के लिए चिंता की बात होगी। अवामी लीग पर लगे प्रतिबंध को मौजूदा सरकार और छात्र संगठन एक अच्छा कदम मानते हैं। वे अवामी लीग पर प्रतिबंध को न्याय की जीत कह रहे हैं। कुछ लोग इस कदम को एक दुष्प्रक्र की तरह देख रहे हैं, क्योंकि अंतरिम सरकार ने अवामी लीग को प्रतिबंधित करके वही काम किया, जो अवामी लीग ने सत्ता में रहते हुए बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी और जमात-ए-इस्लामी जैसे संगठनों के साथ किया था। बांग्लादेश में जिस कथित 'द्वितीय गणतंत्र' की स्थापना शेख हसीना को बेदखल करने के बाद हुई थी, उसी ने देश के सबसे बड़े दल के लोकतांत्रिक अधिकार छीन लिए। यह घटनाक्रम बांग्लादेश में लोकतंत्र को कमजोर करेगा। इतना ही नहीं, यह उस कट्टर इस्लामिक विचारधारा को मजबूत करेगा, जिसके खिलाफ अवामी लीग आवाज उठाती रही है। पड़ोस में कट्टर इस्लामी ताकतों का उभार भारत के हित में भी नहीं। बांग्लादेश में 'सुधारवाद' की भी बात हो रही है, जिसका प्रतिनिधित्व मोहम्मद यूनुस सरकार चलाते हुए कर रहे हैं। यूनुस सरकार विधायी, सिविल और बैंकिंग सेवाओं में सुधार लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन इस काम में उनके समक्ष एक बाधा समय की कमी है। इसी का हवाला देकर यूनुस कई बार यह कह चुके हैं कि बांग्लादेश में चुनाव तब तक नहीं हो सकते, जब तक देश में सुधार पूरी तरह से न हो जाएं। हालांकि तमाम पार्टियां शीघ्र चुनाव की बात कर रही हैं, लेकिन मौजूदा राजनीतिक उथल-पुथल को देखते हुए वहां शीघ्र चुनाव होना मुश्किल लग रहा है। यूनुस भी जल्द चुनाव के लिए तैयार नहीं दिखते। अगर चुनाव हुए तो यूनुस का जाना तय है, क्योंकि वह किसी भी दल से नहीं आते। जिन छात्रों ने उन्हें अंतरिम सलाहकार बनाने में योगदान दिया, उन्होंने अब जातीयो नागरिक पार्टी की स्थापना कर ली है। संभव है वे चुनाव में नए चेहरे को लाएं। इस सबके बीच एक और किरदार है, जिसने सामने आए बिना खुद को मजबूत बनाया है और वह हैं बांग्लादेश सेना के प्रमुख। उन्होंने शेख हसीना के देश से बाहर जाने के बाद कुछ समय के लिए देश की बागडोर भी संभाली थी, लेकिन अब वह पदों के पीछे हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि बांग्लादेश की सेना का शीर्ष नेतृत्व अपने किरदार को नए राजनीतिक ढांचे में किस तरह से देखता है और क्या वह लोकतांत्रिक मूल्यों का सम्मान करते हुए स्वयं को राजनीति से अलग रखेगा? अवामी लीग पर प्रतिबंध कुछ पुरानी घटनाओं की याद दिलाता है। 1971 के मुक्ति संग्राम में पाकिस्तान का समर्थन करने के लिए अवामी लीग द्वारा जमात-ए-इस्लामी पर प्रतिबंध लगाया गया था। अभी पिछले साल तक जमात के शीर्ष नेतृत्व को आजीवन कारावास और मृत्युदंड जैसी कड़ी सजाएं मिलती रहीं, फिर भी वह भिन्न-भिन्न तरीकों से राजनीति में उग्र तरीकों से सक्रिय रहने का प्रयास करती रही।

एक देश-एक संदेश पर भी राजनीति, राष्ट्रीय हित के गंभीर विषय पर विचार जरूरी

पहलगा आतंकी हमले के जवाब में ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान का सच और आतंकवाद पर भारत की जीरो टालरेंस नीति दुनिया को बताने के लिए सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजने की कूटनीतिक पहल में भी दलगत राजनीति दुखद है। विश्व को दिए जाने वाले एक देश-एक संदेश में ऐसी राजनीति से हर हाल में बचा जाना चाहिए था। यह पहली बार नहीं, जब अंतरराष्ट्रीय महत्व के किसी विषय पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल भेजा जा रहा हो। 1994 में कश्मीर पर भारत का पक्ष रखने के लिए नरसिंह राव सरकार ने विपक्ष के नेता अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग भेजा था, जिसमें सलमान खुर्शीद भी थे। 2008 में मुंबई आतंकी हमले के बाद भी मनमोहन सरकार ने बहुदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजे थे। याद नहीं कि राष्ट्रीय हित के किसी मुद्दे पर कभी इतने निचले स्तर की दलगत राजनीति की गई। विदेश नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा पर राजनीतिक सहमति की परंपरा रही है, पर बढ़ती कटुता उस पर ग्रहण लगा रही है। इस कटुता के बावजूद पहलगा आतंकी हमले

के बाद सर्वदलीय बैठक में विपक्ष ने जवाबी कार्रवाई के लिए मोदी सरकार को पूर्ण समर्थन दिया, पर उस बैठक में प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल भी उठे। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। प्रधानमंत्री उस दिन बिहार में एक जनसभा को संबोधित करते हुए आतंकियों को कल्पना से भी बड़ी सजा की चेतावनी दे रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। उसकी अध्यक्षता भी रक्षा मंत्री ने ही की। सभी दलों ने सेना के शौर्य की प्रशंसा करते हुए सरकार को समर्थन दोहराया, पर प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति पर सवाल भी उठाया। आतंकवाद और पाकिस्तान से तनाव के मुद्दे पर राजनीतिक सहमति के बीच भी दलगत दांवपेच दिखते रहे। विपक्ष ने भाजपा की तिरंगा यात्रा को सेना के शौर्य का राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कहा और मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह के कर्नल सोफिया पर आपत्तिजनक बयान पर भी उसे घेरा। इसके बाद सैन्य टकराव थमने और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा उसका श्रेय लेने की कोशिश तथा संसद का विशेष सत्र बुलाने की मांग

पर भी सत्तापक्ष-विपक्ष में तल्लू बढी। इस तल्लू के बीच सात सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल विदेश भेजने के निर्णय पर भी राजनीति शुरू हो गई। चार प्रतिनिधिमंडलों का नेतृत्व राजग, जबकि तीन का नेतृत्व विपक्षी दलों के मोर्चे आइएनडीआई के सदस्य करेंगे। प्रतिनिधिमंडलों में गैर सांसद भी हैं और राजनयिक भी। एक देश-एक संदेश मुखर करने की इस कूटनीतिक रणनीति पर भाजपा कांग्रेस के बीच राजनीतिक रार राजनयिक पृष्ठभूमि वाले पूर्व विदेश राज्य मंत्री शशि थरूर को लेकर छिड़ी। चूंकि हाल के दिनों में थरूर मोदी के प्रशंसक दिखे हैं, इसलिए कांग्रेस को कहना पड़ा कि वह लक्ष्मण-रेखा लांघ रहे हैं। सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरन रिजिजू द्वारा नाम मांगने पर कांग्रेस ने अंतरराष्ट्रीय मामलों के संभवतः सबसे बेहतर जानकार थरूर का नाम नहीं भेजा। सरकार ने खुद उन्हें एक प्रतिनिधिमंडल का नेता बनाया। थरूर ने इसे सम्मान की बात बताया। लगता है रिजिजू जब मल्लिकार्जुन खरगे और राहुल गांधी से बात कर रहे थे, उससे पहले ही वह थरूर को पेशकश कर

चुके थे। इसका संकेत थरूर की एक्स पोस्ट से मिला। सात प्रतिनिधिमंडलों में जिन कांग्रेस नेताओं को शामिल किया गया है, उनमें सिर्फ पूर्व मंत्री आनंद शर्मा का नाम ही पार्टी द्वारा सरकार को भेजे नामों में था। बाकी चार नेताओं-थरूर, सलमान खुर्शीद, मनीष तिवारी और अमर सिंह का चयन खुद सरकार ने किया। ऐसा नहीं कि देश का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रतिनिधिमंडल का चयन सरकार नहीं कर सकती, लेकिन फिर दलों से नाम मांगे जाने का क्या औचित्य? अंतरराष्ट्रीय मामलों में थरूर की समझ पर संदेह नहीं, फिर भी कांग्रेस ने उनके बजाय आनंद शर्मा, गौरव गोर्गई, सैयद नासिर हुसैन और अमरिंदर सिंह राजा के नाम भेजे तो सवाल उठने स्वाभाविक थे। यह मानना सही नहीं होगा कि सरकार ने थरूर का चयन सिर्फ उनकी विशेषज्ञता के आधार पर किया, क्योंकि कुछ सदस्य इस कसौटी पर खरा नहीं उतरते। दरअसल केरल में असें से पांव जमाने की कोशिश कर रही भाजपा को वहां एक लोकप्रिय चेहरा चाहिए, जबकि थरूर अपनी उपेक्षा को लेकर कांग्रेस से निराशा व्यक्त कर चुके हैं।

पृष्ठ 1 का शेष

2007 के बाद नई आवास

इसके लिए 70,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा और 'महा आवास निधि' को बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए करने का निर्णय लिया गया है। इंडब्ल्यूएस, एलआईजी और एमआईजी समूहों को मकान उपलब्ध कराना इसका उद्देश्य है। नीति में वरिष्ठ नागरिकों, महिलाओं, औद्योगिक श्रमिकों और छात्रों की विशिष्ट आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी गई है। रोजगार सृजन में मिलेगी मदद नई आवास नीति से आवास क्षेत्र को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इसमें झुग्गी पुनर्वास से पुनर्विकास तक का एक व्यापक कार्यक्रम निर्धारित किया गया है। शहरी क्षेत्रों में मलिन बस्तियों के पुनर्वास और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास पर भी जोर दिया जाएगा। इससे रोजगार सृजन में भी महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा। इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय स्थापित किया जाएगा। इस बीच, नई आवास नीति के इस निर्णय का सामाजिक और आर्थिक क्षेत्रों में स्वागत किया जा रहा है। सरकार के इस फैसले से उम्मीद जगी है कि लाखों परिवारों का अपना घर होने का सपना साकार होगा। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजीत पवार और अन्य कैबिनेट सदस्य बैठक में उपस्थित थे। दो दशक बाद नीति: राज्य की पिछली आवास नीति 2007 में जारी की गई थी। करीब 18 साल बाद आवास नीति की घोषणा की गई है।

मुंबई मीठी नदी सफाई घोटाले

मीट्रिक टन गाद निकालने का रेट 1693 रुपये था, लेकिन हकीकत में 2100 रुपये तक का भुगतान किया गया। दक्षता विभाग के कहने पर बाद में दुबारा से पैसे कम किए गए। अभियंताओं को मिला कमीशन जांच में यह भी सामने आया है कि ठेकेदारों को गाद निकालने वाली मशीनरी किराए पर देने से पहले, BMC अभियंता रामगुडे, बेंद्रे और तायशेट्टे ने मिडलमैन केतन कदम और जय जोशी के साथ बैठक की थी। इस बैठक में तय हुआ कि मशीनरी मेट्रोप कंपनी से खरीदने का दिखावा किया जाएगा, लेकिन असल में उसे किराए पर दिया जाएगा और बदले में अभियंताओं को कमीशन मिलेगा। BMC की ओर से टेंडर में मशीन खरीदने की शर्त शामिल थी, लेकिन इस पूरी योजना को मोड़कर, किराए पर मशीन देने की हरी झंडी दे दी गई जिससे मशीनरी किराए की आड़ में करोड़ों का कमीशन कमाया गया।

वीडियो विज्ञापन बैन और होर्डिंग का

ऐसा हादसा न हो. बीएमसी ने नई नीति के तहत कार्रवाई शुरू की है, जिसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं. होर्डिंग के आकार से लेकर बीमा तक की नीति बनाई गई है. बीएमसी ने सितंबर 2024 से अब तक शहरभर से 1,963 अवैध विज्ञापन, पोस्टर, बैनर और झंडे हटाए, जिनमें 576 राजनीतिक और 473 धार्मिक होर्डिंग्स शामिल हैं. अकेले आजाद मैदान क्षेत्र से 750 से अधिक हटाए गए हैं. मुंबई में फिलहाल 1,025 वैध होर्डिंग्स हैं, इनमें 573 बिना लाइट, 382 लाइट वाले और 70 डिजिटल LED होर्डिंग्स हैं, जिनसे BMC को हर साल करीब 100 करोड़ का राजस्व प्राप्त होता है. बिना सर्टिफिकेट वाले लाइसेंस होंगे रह वहीं नई होर्डिंग नीति 2024, अगस्त से लागू हुई है, जो 2008 की पुरानी नीति को हटाकर लाई गई है.

पार्किंग होने पर ही खरीद पाएंगे कार...

सरनाईक ने कहा कि अब जो नए खरीदार होंगे उनके पास यदि नगर निकाय से पार्किंग आवंटन प्रमाण पत्र नहीं है, तो उनके नाम से नए वाहनों का पंजीकरण नहीं किया जाएगा। पार्किंग निर्माण को मंजूरी मिलेगी परिवहन मंत्री ने कहा कि एमएमआर में पार्किंग की कमी है। उन्होंने कहा कि निर्धारित मैदानों के नीचे पार्किंग सुविधा के निर्माण की अनुमति देने के प्रस्ताव पर काम कर रहा है। इस कदम से शहर की हरियाली को प्रभावित किए बिना अधिक पार्किंग स्थान बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है। सरनाईक ने शहरी गतिशीलता में सुधार के प्रयासों के तहत पॉड टैक्सी प्रणाली शुरू करने की महाराष्ट्र की योजना के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि पॉड टैक्सी परियोजना पर मेरे समक्ष एक प्रस्तुति दी गई। मैंने वडोदरा का दौरा किया है, जो दुनिया की पहली व्यावसायिक रूप से तैयार सस्पेंडेड पॉड-कार परिवहन प्रणाली की मेजबानी करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा कि राज्य मेट्रो नेटवर्क के साथ अंतिम मील कनेक्टिविटी में सुधार के लिए मीरा-भयंदर और बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स (बीकेसी) में इसी तरह के पॉड टैक्सी नेटवर्क पर विचार कर रहा है। चेन्नई ने एक पार्किंग नीति शुरू की है, जिसमें नए वाहन पंजीकरण के लिए पार्किंग प्रमाण अनिवार्य करने की सिफारिश की गई है। निजी वाहनों के उपयोग पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से बनाई गई इस योजना में पार्किंग प्रबंधन इकाई, निर्दिष्ट क्षेत्र और परिवर्तनीय शुल्क शामिल हैं।

उच्च न्यायिक सेवाओं में LDCE आरक्षण 25% होगा; 2007 बैच की नौसेना अधिकारी को स्थायी कमीशन मिलेगा

सुप्रीम कोर्ट ने उच्च न्यायिक सेवा या जिला न्यायाधीश के कैडर में पदोन्नति के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा (एलडीसीई) के लिए आरक्षित कोटा भी 10% से बढ़ाकर 25% कर दिया। सीजेआई जस्टिस बीआर गवई व जस्टिस एजी मसीह की पीठ ने कहा, इससे न्याय प्रशासन पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। उच्च न्यायपालिका में 25% पद बाहर से सीधी भर्ती से भरे जाते हैं, जबकि 50% योग्यता-सह-वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति से भरे जाते हैं। एलडीसीई में न्यायिक अधिकारी अनुभव या वरिष्ठता की परवाह किए बिना इसे पास करके एडीजे बन सकते हैं। बहुत हुआ, 2007 बैच की अधिकारी को स्थायी कमीशन दे नौसेना: सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्देश के बावजूद 2007 के एक शॉर्ट सर्विस कमीशन अधिकारी को स्थायी कमीशन न देने पर नौसेना को फटकार लगाई और कहा, बहुत हुआ। नौसेना के अधिकारी अपना अहंकार छोड़ें और इस अधिकारी को स्थायी कमीशन दें। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने 2007



बैच की जज एडवोकेट जनरल (विधिक) विभाग की अधिकारी सीमा चौधरी को एक सप्ताह में स्थायी कमीशन देने पर विचार करने के लिए कहा। पीठ ने नौसेना अधिकारियों और केंद्र की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता आर. बालासुब्रमण्यम से कहा, बहुत हो गया। कृपया अपना व्यवहार का समय देंगे। क्या संबंधित अधिकारी सोचते हैं कि वे न्यायालय के आदेशों को नजरअंदाज कर सकते हैं? आप किस तरह के अनुशासित बल हैं? चयन बोर्ड की कार्यवाही और अधिकारी की वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट का अवलोकन करने वाली पीठ ने पूछा कि जब अधिकारियों ने

दावा किया था कि उन्होंने सभी मानक हासिल कर लिए हैं, तो उन्हें स्थायी कमीशन में क्यों नहीं लिया गया। पीठ ने कहा, संबंधित अधिकारियों को अपना अहंकार त्यागना होगा। आप कैसे कह सकते हैं कि वह सभी पहलुओं में फिट हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें स्थायी कमीशन में नहीं ले सकते? इस अदालत का स्पष्ट निष्कर्ष है कि उनके मामले पर अलग से विचार किया जाना चाहिए। फिर अब तक उन पर विचार क्यों नहीं किया गया? फिलपकार्ट को एकाधिकार बनाने में महारत, हमें छोटी कंपनियों की चिंता; शीर्ष अदालत करेगी एकाधिकार बनाने के मुद्दे की जांच सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ई-कॉमर्स क्षेत्र की प्रमुख कंपनी फिलपकार्ट

एकाधिकार बनाने के लिए जानी जाती है। उसे इसमें महारत हासिल है। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे बाजार में छोटी कंपनियों के भविष्य को लेकर चिंता है। शीर्ष अदालत ने राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील न्यायाधिकरण (एनसीएलएटी) के आदेश से शुरू हुए विवाद के निपटारे में मदद के लिए वकील उदयादित्य बनर्जी को न्यायमित्र नियुक्त किया। एनसीएलएटी ने निष्पक्ष व्यापार नियामक भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) को फिलपकार्ट के खिलाफ उसके प्रभुत्वपूर्ण स्थिति के दुरुपयोग के लिए जांच शुरू करने को कहा था। जस्टिस सूर्यकांत व जस्टिस एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने इस बात पर हैरानी जताई कि फिलपकार्ट पर अनुचित व्यापार व्यवहार का आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर्स एसोसिएशन (एआईओवीए) का कहीं पता नहीं चला। उसके वकीलों को संस्था से कोई निर्देश नहीं मिला था। एआईओवीए की ओर से पेश अधिवक्ता उदयादित्य बनर्जी ने कहा कि यह संभव है कि संगठन को भंग कर दिया गया हो या अब उसका अस्तित्व ही न हो।

अहमदाबाद में बुलडोजर का मेला; आज भी खाली कराई जा रही 2.5 लाख वर्ग मीटर जमीन, 3000 पुलिसकर्मी भी तैनात



गुजरात के अहमदाबाद के चंदोला इलाके में चल रहे अतिक्रमण हटाओ अभियान का दूसरा चरण आज दूसरे दिन भी जारी है। इस अभियान में प्रशासन की तरफ से बड़े पैमाने पर अवैध निर्माणों को हटाया जा रहा है। बता दें कि यह अभियान कुल 2.5 लाख वर्ग मीटर से अधिक जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए चलाया जा रहा है। इसके मद्देनजर कई बुलडोजर और 3000 से अधिक पुलिस कर्मियों को मौके पर तैनात किया गया है।

'अब तक 99.9% काम पूरा'

मामले में जानकारी देते हुए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच के संयुक्त पुलिस आयुक्त (जेसीपी) जयपाल सिंह राठौड़ ने बताया कि चंदोला इलाके में अभियान का दूसरा चरण कल से शुरू हुआ है। इसके बाद अब तक 99.9 प्रतिशत तोड़फोड़ का काम पूरा हो चुका है। अब कुछ धार्मिक ढांचे हटाए जा रहे हैं। जेसीपी ने जनता से अफवाहों पर विश्वास न करने की अपील की। साथ ही प्रशासन पूरी पारदर्शिता और कानून के दायरे में रहकर काम कर रहा है।

शांतिपूर्ण ढंग से चल रही कार्रवाई

इसके साथ ही मामले प्रशासन का कहना है कि यह कार्रवाई बिना किसी हिंसा के शांतिपूर्वक चल रही है। साथ ही प्रशासन ने स्थानीय लोगों से सहयोग की अपील की गई है। इस अभियान का उद्देश्य शहर की सरकारी जमीन को अवैध कब्जों से मुक्त कराकर उसका उचित उपयोग सुनिश्चित करना है।

'यह समझने की गलती थी', मणिपुर में सरकारी बस पर राज्य का नाम छिपाने पर संबित पात्रा ने दी सफाई



मणिपुर में सरकारी बस पर राज्य का नाम छिपाने को लेकर हुए विवाद के बाद भाजपा नेता और पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रभारी संबित पात्रा ने कहा कि यह मामला 'समझने की गलती' थी। वहीं इस मामले में मीडिया संगठनों ने राज्यपाल को एक ज्ञापन भी भेजा है।

मणिपुर में सुरक्षा बलों की तरफ से बस पर राज्य का नाम छिपाने के मामले में मंचे बवाल पर भाजपा की तरफ से सफाई दी गई है। भाजपा के पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रभारी संबित पात्रा ने कहा कि मणिपुर में सुरक्षा बलों की तरफ से एक सरकारी बस पर राज्य का नाम छिपाने का मामला 'समझने की गलती' थी। उन्होंने यह भी कहा कि मणिपुर की अखंडता अविचल है और इसे लेकर कोई समझौता नहीं होगा। क्या है पूरा मामला? यह घटना इफाल पूर्वी जिले के ग्वालताबी में हुई, जहां पत्रकारों को 'शिरुई लिली' उत्सव कवरेज के लिए भेजा गया था। सुरक्षा बलों ने बस को रोका और बस के कांच पर लिखे मणिपुर राज्य परिवहन के नाम को एक सफेद कागज से ढकने का आदेश दिया।

केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंची स्टालिन सरकार, शिक्षा योजना का फंड रोके जाने पर दायर की याचिका



तमिलनाडु की स्टालिन सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। अपनी याचिका में राज्य सरकार ने कहा है कि, केंद्र ने समग्र शिक्षा योजना के तहत 2000 करोड़ से ज्यादा फंड रोके हैं। तमिलनाडु सरकार ने केंद्र सरकार के खिलाफ

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। यह याचिका समग्र शिक्षा योजना के तहत 2000 करोड़ से ज्यादा फंड रोके जाने को लेकर है। राज्य सरकार का आरोप है कि उसने नई शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 को लागू नहीं किया, इसलिए केंद्र ने फंड जारी नहीं किया।

याचिका में क्या कहा गया है?

मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली डीएमके सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार को 2000 करोड़ से ज्यादा की बकाया राशि तत्काल जारी करने का आदेश दिया जाए। इस रकम पर छह फीसदी सालाना ब्याज के साथ भुगतान किया जाए। केंद्र की तरफ से एनईपी लागू करने के बहाने फंड रोकने की कार्रवाई को 'असंवैधानिक, अवैध, मनमानी और गैर-जिम्मेदाराना' घोषित किया जाए।

तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से साफ तौर पर कहा है कि एनईपी 2020 और प्रधानमंत्री श्री स्कूल योजना तमिलनाडु पर बाध्यकारी (बार्डिंग) नहीं हो सकती। केंद्र को 'मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2010' (राइट टू एजुकेशन एक्ट) के तहत अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए हर शैक्षणिक वर्ष की शुरुआत से पहले 60% खर्च की राशि समय पर देनी चाहिए।

महाराष्ट्र में सीजेआई गवई स्थायी राजकीय अतिथि नामित; सरकार ने प्रोटोकॉल जारी किया

महाराष्ट्र में सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस (सीजेआई) बीआर गवई को स्थायी राजकीय अतिथि नामित किया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली सरकार ने प्रोटोकॉल जारी किया है।

बता दें कि सीजेआई ने मुंबई यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन पर नाराजगी जताई थी।

महाराष्ट्र सरकार ने भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) की मुंबई और राज्य के अन्य हिस्सों की यात्रा के दौरान आधिकारिक शिष्टाचार का पालन सुनिश्चित करने के लिए प्रोटोकॉल दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत सीजेआई को स्थायी राजकीय अतिथि नामित किया गया है। राज्य सरकार की ओर से मंगलवार को जारी विज्ञप्ति में कहा गया है कि सीजेआई बीआर गवई को अब आधिकारिक तौर पर महाराष्ट्र में स्थायी राजकीय अतिथि के रूप में नामित किया गया है।

21 साल पुराने नियमों का हवाला



दिया राज्य सरकार ने इस फैसले के लिए राज्य अतिथि नियम, 2004 का हवाला दिया है। लेकिन माना जा रहा है कि राज्य की ओर से यह कदम सीजेआई गवई की ओर से उनकी यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल उल्लंघन पर नाराजगी व्यक्त किए जाने के बाद उठाया गया है। सीजेआई बनने के बाद जस्टिस गवई रविवार को पहली बार मुंबई आए, तब उनकी अगवानी के लिए राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक या मुंबई पुलिस के आयुक्त में से कोई भी उपस्थित नहीं था। राज्य के कैबिनेट मंत्री चंद्रशेखर बावनकुले ने इस प्रोटोकॉल चूक के लिए सीजेआई

को फोनकर माफी मांगी थी। हालांकि, मामला तूल पकड़ने पर सीजेआई गवई ने प्रोटोकॉल चूक को मामूली बात बताया और कहा कि इसे तूल न दिया जाए और मामला यहीं समाप्त किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने एक बयान में बताया कि सभी संबंधित अधिकारी खेद जता चुके हैं। क्या है राज्य अतिथि नियम महाराष्ट्र राज्य अतिथि नियम, 2004 के अनुसार, घोषित राज्य अतिथि की सूची में शामिल गणमान्य व्यक्तियों या ऐसे माने जाने वाले गणमान्य व्यक्तियों को राज्य प्रोटोकॉल उप-विभाग की ओर से हवाई अड्डों पर स्वागत और विदाई की व्यवस्था की जाती है।

जिला स्तर पर जिला कलेक्टर कार्यालय नामित प्रोटोकॉल अधिकारियों के माध्यम से इसी प्रकार की व्यवस्था सुनिश्चित करता है। इसके अनुसार, भारत के मुख्य न्यायाधीश को राज्य अतिथि नियम, 2004 के अनुसार सभी प्रोटोकॉल संबंधी सुविधाएं प्राप्त होती रहेंगी, जिसमें यात्रा के दौरान आवास, वाहन व्यवस्था और पूरे राज्य में सुरक्षा शामिल है। मामूली मुद्दे को अनावश्यक तूल न दें

इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से एक बयान जारी किया गया है। इसमें कहा गया है कि सीजेआई की महाराष्ट्र यात्रा के दौरान प्रोटोकॉल से जुड़ी खबरें मीडिया में प्रकाशित हो रही हैं। सभी संबंधित लोग पहले ही खेद जता चुके हैं।

सीजेआई ने कहा है कि यह एक मामूली मुद्दा है, इसे अनावश्यक रूप से तूल न दिया जाए। सीजेआई ने सभी से आग्रह किया है कि इस मामले को अब समाप्त मान लिया जाए।

BJP IT सेल प्रमुख अमित मालवीय, अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कर्नाटक में FIR; आपराधिक अभियान चलाने के आरोप



भाजपा के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और पत्रकार अर्णब गोस्वामी के खिलाफ कर्नाटक में एफआईआर दर्ज कराई गई है। शिकायत करने वाले ने दोनों पर आपराधिक अभियान चलाने के आरोप लगाए हैं। शिकायत में कहा गया है कि दोनों ने तुर्किये के इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को कांग्रेस का कार्यालय बताकर दुर्भावनापूर्ण और झूठे दावे किए। भाजपा आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय और रिपब्लिक टीवी के प्रधान संपादक अर्णब गोस्वामी के खिलाफ मंगलवार को झूठी जानकारी फैलाने के लिए बंगलूरु में एफआईआर दर्ज की गई।

पुलिस के अनुसार, यह मामला हाई ग्रांड्स पुलिस स्टेशन में इंडियन यूथ कांग्रेस (IYC) के कानूनी सेल प्रमुख श्रीकांत स्वरूप बीएन की शिकायत पर दर्ज किया गया। शिकायत में मालवीय और गोस्वामी पर बीएनएस की धारा 192 (दंगा भड़काने के इरादे से उकसाना) और 352 (शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान) के तहत मामला दर्ज किया गया। स्वरूप ने आरोप लगाया कि मालवीय और गोस्वामी ने झूठी जानकारी प्रसारित करने के लिए एक जघन्य और आपराधिक अभियान चलाया। उन्होंने दावा किया कि दोनों ने तुर्किये के इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (आईएनसी) का कार्यालय बताकर दुर्भावनापूर्ण ढंग से झूठा दावा फैलाया। शिकायतकर्ता श्रीकांत स्वरूप ने कहा कि झूठी और भ्रामक जानकारी प्रसारित करने का उद्देश्य भारत की जनता को धोखा देना, एक प्रमुख राजनीतिक संस्था को बदनाम करना, राष्ट्रीय भावनाओं को भड़काना, सार्वजनिक अशांति को बढ़ावा देना और राष्ट्रीय सुरक्षा व लोकतांत्रिक अखंडता को कमजोर करना था।

मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा! 4 दिन के अंदर केरल में एंटी, मुंबई समेत महाराष्ट्र के 'इन' इलाकों में ऑरेंज अलर्ट

मुंबई: भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने कहा है कि मानसून (Monsoon2025) इस हफ्ते के अंत तक केरल में आ जाएगा। मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। केरल, तमिलनाडु और पूर्वोत्तर राज्यों में भी मानसून आ सकता है। इसके साथ ही महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। बेमौसम बारिश से अहिल्यानगर जिले में किसानों को भारी नुकसान हुआ है। IMD के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम और पूर्वोत्तर दोनों शाखाओं के तेजी से आगे बढ़ने के कारण मानसून के लिए अनुकूल माहौल बन रहा है। अगले चार से पांच दिनों में मानसून दक्षिण अरब सागर के कुछ और हिस्सों, मालदीव और कोमोरिन के बचे हुए इलाकों, लक्षद्वीप के कुछ हिस्सों, केरल, तमिलनाडु, बंगाल की खाड़ी के दक्षिणी और मध्य भाग, बंगाल की खाड़ी के पूर्वोत्तर भाग और पूर्वोत्तर राज्यों में प्रवेश कर सकता है। मुंबई में भारी बारिश की चेतावनी मौसम विभाग की अधिकारी शुभांगी भुते ने बताया कि अरब सागर में एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र बन रहा है। इसके चलते गुरुवार को कम दबाव का क्षेत्र बनेगा। इसका असर महाराष्ट्र में दिखेगा। मुंबई, दक्षिण कोंकण और दक्षिण मध्य महाराष्ट्र में गरज के साथ भारी बारिश हो सकती है। इस दौरान हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है। पुणे घाट क्षेत्र में गुरुवार और शुक्रवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। कोल्हापुर और सतारा घाट क्षेत्र में गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रत्नागिरी में आज से शुक्रवार तक ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। सिंधुदुर्ग में गुरुवार और शनिवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। रायगढ़ में गुरुवार को ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

'ममता बनर्जी सरकार की क्रूरता हुई उजागर', मुर्शिदाबाद हिंसा पर तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट पर भाजपा हमलावर

भाजपा ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा पर तथ्य खोज समिति की रिपोर्ट को लेकर टीएमसी सरकार पर निशाना साधा है। इसके साथ सुधांशु त्रिवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर को छुटपुट घटना कहना सिर्फ निंदनीय ही नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का अपमान है। भाजपा ने वक्फ (संशोधन) अधिनियम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान भड़की मुर्शिदाबाद हिंसा से निपटने के तरीके को लेकर ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार पर तीखा हमला किया। पार्टी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने बुधवार को उन्होंने कहा कि तथ्य-खोजी एसआईटी की रिपोर्ट से हिंदुओं के प्रति सरकार की क्रूरता



का पता चला है। उन्होंने कहा कि हिंसा पर एसआईटी की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि हिंदुओं को निशाना बनाकर हिंसा की गई थी और इसमें टीएमसी नेता शामिल थे। हिंसा के दौरान पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सुधांशु त्रिवेदी ने उन पर टीएमसी नेताओं की कार्रवाई की अनदेखी करने का आरोप लगाया। उन्होंने

कहा, 'कुछ मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, मुर्शिदाबाद हिंसा पर एसआईटी की रिपोर्ट ने स्पष्ट रूप से और स्पष्ट रूप से संकेत दिया है कि हिंदुओं को निशाना बनाकर हिंसा की गई थी और इसमें टीएमसी नेता शामिल थे और पुलिस का रवैया हिंसा को रोकने के बजाय टीएमसी नेताओं की कार्रवाई की अनदेखी करने वाला

प्रतीत होता है।' उन्होंने कहा, 'मुर्शिदाबाद से पहलगाम तक हिंदुओं को निशाना बनाकर उनके खिलाफ हिंसा का सिलसिला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। मुर्शिदाबाद हिंसा में जिस तरह से तथ्य सामने आ रहे हैं, उससे ममता बनर्जी सरकार की हिंदुओं के प्रति क्रूरता और कट्टरपंथियों के प्रति असीम लगाव का पता चलता है।'

यह तब हुआ जब कलकत्ता उच्च न्यायालय की तरफ से गठित तथ्य-खोजी समिति ने पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा पर अपनी रिपोर्ट पेश की, जिसमें बताया गया कि हिंसा के दौरान बेतबाना गांव में 113 घर बुरी तरह प्रभावित हुए।

दक्षिण के बाद पूर्वोत्तर में मौसम का कहर; भारी बारिश से गुवाहाटी हुआ जलमग्न, आम जनजीवन प्रभावित

असम के गुवाहाटी में रातभर हुई भारी बारिश के कारण कई सड़कें और रिहायशी इलाके जलमग्न हो गए, जिससे मंगलवार को वाहनों की आवाजाही बाधित हुई और शहर के निवासियों को असुविधा हुई। शहर के कुछ इलाकों में लोगों को घुटनों तक पानी से गुजरते देखा गया, जबकि कई इलाकों में पानी का स्तर छाती तक पहुंच गया। वहीं 10 से ज्यादा इलाके जू रोड, नवीन नगर, हाटीगांव, गणेशगुड़ी, गीता नगर, मालीगांव, हिदायतपुर, गुवाहाटी क्लब, उलुबारी, लचित नगर, चांदमारी और पंजाबरी में बाढ़ की खबर है। रातभर हुई बारिश के कारण जीएस रोड जोराबाट, तरुण नगर, जटिया, ज्योतिकुची, घोरामारा, वीआईपी रोड, रुक्मिणी गांव, सर्वे और छत्रीबाड़ी समेत कई इलाकों में जलभराव हो गया।

शहर में कई स्कूलों में स्थगित की परीक्षाएं कई स्कूलों, जहां आंतरिक परीक्षाएं चल रही हैं, ने शहर भर में बाढ़ वाले परिसर और सड़कों के कारण सुबह बंद करने की घोषणा की है, क्योंकि अधिकांश स्कूल बसों ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं। वहीं कई स्थानों पर जलभराव वाली सड़कों पर कई वाहन फंसे हुए हैं, जबकि मरीजों को ले जा रही



एम्बुलेंस भी फंसी हुई हैं। जैसे-जैसे दिन चढ़ता गया, शहर के लगभग सभी इलाकों से ट्रैफिक जाम की खबरें आईं और सड़कों पर जलभराव के कारण वाहन फंसे रहे।

2-3 दिनों तक असम में खराब मौसम की भविष्यवाणी वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने अगले 2-3 दिनों तक असम में खराब मौसम की भविष्यवाणी की है, जिसमें राज्य के कई हिस्सों में भारी से बहुत भारी बारिश होने की उम्मीद है। एक आधिकारिक विज्ञापन में कहा गया है, '20 मई, 2025 को दर्ज किए गए बारिश के आंकड़ों के अनुसार, गुवाहाटी और उसके आसपास के कई स्थानों पर पहले से ही पर्याप्त बारिश हो चुकी है, जिसमें गुवाहाटी एडब्ल्यूएस स्टेशन पर 112.5 मिमी बारिश शामिल है।' मौसम के पैटर्न से पता चलता है कि आने वाले दिनों में असम के पश्चिमी

और दक्षिणी दोनों हिस्सों में और अधिक तीव्र वर्षा होने की संभावना है, जो संभावित रूप से अलग-अलग स्थानों पर 200 मिमी तक पहुंच सकती है।

गुवाहाटी में जलभराव और आमजन के लिए निर्देश इसमें कहा गया है कि 'गुवाहाटी में लगातार बारिश से जलभराव बढ़ सकता है, वाहनों की आवाजाही धीमी हो सकती है और संवेदनशील इलाकों में पेड़ गिरने और स्थानीय भूस्खलन का खतरा बढ़ सकता है।' बयान में कहा गया है कि नागरिक निकाय के अधिकारी स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणालियों को अलर्ट पर रखा जा रहा है। 'लोगों को सभी आवश्यक सावधानी बरतने और सतर्क रहने की सलाह दी जाती है। दैनिक यात्रियों और लंबी दूरी के यात्रियों से अनुरोध है कि वे अपनी दिनचर्या

तदनुसार योजना बनाएं, तीव्र वर्षा के दौरान अनावश्यक आवाजाही से बचें।'

बाढ़ग्रस्त इलाकों में पहुंचे मंत्री जयंत मल्ला बरुआ सरकार ने निचले इलाकों और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ या मिट्टी के कटाव के किसी भी संकेत के लिए सतर्क रहने की सलाह दी है। इसमें कहा गया है कि 'लोगों से आधिकारिक मौसम अपडेट पर नजर रखने और स्थानीय अधिकारियों की तरफ से जारी की गई सलाह का पालन करने का भी आग्रह किया जाता है ताकि इस लंबे समय तक चलने वाली बारिश के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।' इससे पहले सुबह में, आवास और शहरी मामलों के मंत्री जयंत मल्ला बरुआ ने दोपहिया वाहन पर सवार होकर कुछ बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया।

इस दौरान मंत्री ने कहा, 'गुवाहाटी में कल रात भारी बारिश हुई और आज भी इसके जारी रहने का अनुमान है। हमने मेघालय की पहाड़ियों से आने वाले बारिश के पानी के कारण शहर में अतिरिक्त समस्याएं देखी हैं। हमारे पास कुछ स्लुइस गेट हैं, लेकिन वे पानी के इतने बड़े प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।'

युसुफ पठान की जगह संसदीय प्रतिनिधिमंडल में होंगे अभिषेक बनर्जी; TMC का करेंगे प्रतिनिधित्व



'ऑपरेशन सिंदूर' के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अब दुनिया में पाकिस्तान को बेनकाब करने की तैयारी कर ली है। इसके लिए सरकार दुनिया के अलग अलग देशों में अपना प्रतिनिधिमंडल भेज रही है। सांसदों के साथ प्रतिनिधिमंडल दुनियाभर के देशों में जाकर आतंकवाद के मुद्दे पर भारत का पक्ष रखेंगे और पाकिस्तान का पर्दाफाश करेंगे। हर प्रतिनिधिमंडल चार से पांच देशों का दौरा करेगा।

'ऑपरेशन सिंदूर' के सिलसिले में संसदीय प्रतिनिधिमंडल में तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और पार्टी सांसद अभिषेक बनर्जी पार्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे। टीएमसी ने 'X' पर लिखा, 'हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारी अध्यक्ष ममता बनर्जी ने आतंकवाद के खिलाफ भारत की वैश्विक पहुंच के लिए सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल में तृणमूल कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी को नामित किया है।'

तृणमूल ने आगे कहा कि ऐसे समय में जब दुनिया को आतंकवाद के बढ़ते खतरे का सामना करने के लिए एकजुट होना चाहिए, अभिषेक बनर्जी का प्रतिनिधिमंडल से जुड़ना दृढ़ विश्वास और स्पष्टता दोनों लाता है। उनकी उपस्थिति न केवल आतंकवाद के खिलाफ बंगाल के दृढ़ रुख को दर्शाएगी, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की सामूहिक आवाज को भी मजबूत करेगी।

32 देशों और बेल्जियम के बुसेल्स में यूरोपीय संघ के मुख्यालय का दौरा बैजयंत पांडा (भाजपा), रविशंकर प्रसाद (भाजपा), संजय कुमार झा (जदयू), श्रीकांत शिंदे (शिवसेना), शशि थरूर (कांग्रेस), कनिमोझी (डीएमके) और सुप्रिया सुले (एनसीपी-एसपी) के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल कुल 32 देशों और बेल्जियम के बुसेल्स में यूरोपीय संघ के मुख्यालय का दौरा करेंगे।

महंगाई की मार, सीआरपीएफ के 3 लाख से ज्यादा कार्मिकों को बतौर 'मैस' एडवांस जमा कराने होंगे 6500 रुपये



देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीआरपीएफ' को महंगाई का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते बल महानिदेशालय ने अधीनस्थ अधिकारी (एसओ) और अन्य रैंक (ओआर) के तहत आने वाले कार्मिकों के लिए मैस एडवांस राशि में बढ़ोतरी कर दी है। मौजूदा समय में यह राशि पांच हजार रुपये है। अब इस राशि को 65 सौ रुपये कर दिया गया है। सीआरपीएफ महानिदेशालय ने 19 मई को उक्त आदेश जारी किया है।

राशन मनी अलाउंस के रेटों में बदलाव किया गया था केंद्रीय गृह मंत्रालय की पुलिस-2 डिवीजन द्वारा 11 फरवरी को सीएपीएफ के अराजपत्रित लड़ाकू पर्सनल, जिसमें आईबी और दिल्ली पुलिस के कर्मचारी भी शामिल हैं, के लिए राशन मनी अलाउंस के रेटों में बदलाव किया गया था। इसके तहत एक अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 तक केंद्रीय अर्धसैनिक बल, आईबी और दिल्ली पुलिस के कार्मिकों के लिए राशन मनी भत्ता 150.04 रुपये प्रति कार्मिक/प्रतिदिन त किया गया था। एडवांस के तौर पर 5000 रुपये देने पड़ते हैं।

मौजूदा समय में सीआरपीएफ के अधीनस्थ अधिकारी (एसओ) और अन्य रैंक (

'हर जिले में नियुक्त करें संरक्षण अधिकारी..', कोर्ट का राज्यों-केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश

सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया कि वे जिला व तालुका स्तर पर संरक्षण अधिकारी नियुक्त करें ताकि घरेलू हिंसा पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। शीर्ष कोर्ट ने उन्हें मुफ्त कानूनी सहायता के अधिकार का प्रचार करने को भी कहा। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) को निर्देश दिया कि वे जिला और तालुका स्तर पर महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों की पहचान करें और उन्हें संरक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त करें। संरक्षण अधिकारी का काम घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करना है।



जस्टिस बी.वी.नागरत्ना और जस्टिस सत्येश चंद्र शर्मा की बेंच ने राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और महिला एवं बाल/समाज कल्याण विभागों के सचिवों को निर्देश दिया कि वे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत अधिकारियों की संरक्षण अधिकारी के रूप में नियुक्त सुनिश्चित करें। 'मीडिया के जरिए करें घरेलू हिंसा

अधिनियम के प्रावधानों का प्रचार' शीर्ष कोर्ट ने कहा, 'वे अधिनियम के प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़ाने, अधिनियम के तहत सेवाओं का प्रभावी समन्वय सुनिश्चित करने और इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए मीडिया के जरिए व्यापक प्रचार प्रसार करेंगे और धारा 11 के तहत अपने दायित्वों को निभाने के लिए कदम उठाएंगे।'

'छह हफ्तों के भीतर पूरी की जाए प्रक्रिया'

बेंच ने निर्देश दिया कि जहां संरक्षण अधिकारी नियुक्त नहीं किए गए हैं, वहां यह प्रक्रिया छह हफ्तों के भीतर पूरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा, राज्य यह सुनिश्चित करेंगे कि सेवा प्रदाता, सहायता समूह और आश्रय गृह पीड़ित महिलाओं के लिए उपलब्ध हों। राज्य इस उद्देश्य के लिए आश्रय गृहों की पहचान भी करेंगे। 'कानूनी सहायता के अधिकार के बारे में जागरूक करें' बेंच ने विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम के तहत महिलाओं के अधिकार को महत्व देते हुए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) के सदस्य सचिव को निर्देश दिया

पिकलबॉल में हाथ आजमाते नजर आए कोहली और अनुष्का, कार्तिक-दीपिका भी दिखे; आरसीबी ने साझा किया पोस्ट



भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज विराट कोहली और अनुष्का शर्मा की जोड़ी पिकलबॉल खेलती नजर आई। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के टीम बॉन्डिंग इवेंट में कोहली-अनुष्का की जोड़ी ने पिकलबॉल खेला और जोड़दोर के तौर पर इसमें हिस्सा लिया। आरसीबी का अब सनराइजर्स हैदराबाद से सामना होना है और इस मैच से पहले टीम के सदस्यों ने

पिकलबॉल में हाथ आजमाया। अनुष्का के साथ बनाई जोड़ी पिकलबॉल खेलने के लिए आरसीबी के खिलाड़ियों के अलावा सहायक स्टाफ और उनके परिवार के सदस्य भी आए। आरसीबी ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट किया है जिसमें कोहली अंक हासिल करने के बाद अनुष्का को बधाई देते दिख रहे हैं। इन दोनों के अलावा आरसीबी के बल्लेबाजी मेंटर

दिनेश कार्तिक और उनकी पत्नी दीपिका पल्लीकल भी मौजूद रहीं। दीपिका भारत की स्टार स्क्वाश खिलाड़ी हैं। आरसीबी के लिए शानदार रहा है और टीम प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। सनराइजर्स और आरसीबी के बीच मुकाबला बंगलूरु में होना था, लेकिन बारिश की संभावना को देखते हुए इसे लखनऊ स्थानांतरित कर दिया था। इससे पहले उसका कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) के खिलाफ

17 मई को खेला गया मुकाबला बारिश में धुल गया था। आरसीबी और हैदराबाद के बीच आईपीएल 2025 का 65वां मुकाबला बंगलूरु में खेला जाना था, लेकिन अब इसे लखनऊ के भारत रत्न श्री अटल विहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में कराने का फैसला लिया गया है। आईपीएल ने बताया कि बंगलूरु में खराब मौसम को देखते हुए लखनऊ में इस मैच को स्थानांतरित करने का फैसला किया गया है। आरसीबी की टीम को बंगलूरु में बारिश के कारण परेशानी का सामना करना पड़ रहा था क्योंकि वह मैदान पर अभ्यास नहीं कर पा रही थी, इसलिए पिकलबॉल इवेंट से उसके खिलाड़ियों को राहत मिली है।

बांग्लादेश के खिलाफ टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम का एलान, बाबर-रिजवान की फिर हुई अनदेखी

पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने बुधवार को इस महीने होने वाली घरेलू टी20 सीरीज के लिए पाकिस्तान की टीम का एलान कर दिया। बांग्लादेश के खिलाफ होने वाली इस सीरीज के लिए तेज गेंदबाज हसन अली की टीम में वापसी हुई है जबकि सीनियर बल्लेबाज बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को एक बार फिर अनदेखी का सामना करना पड़ा है।

Trending Videos

पीएसएल में मचाया था धमाल

हसन ने लगभग तीन साल में सिर्फ एक टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है। 2024 में आयरलैंड के खिलाफ डबलिन में खेले गए मैच में उन्होंने तीन ओवर में 42 रन लुटाए थे जबकि उन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। हसन



ने पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स का प्रतिनिधित्व करते हुए 15 विकेट चटकाए हैं। रिजवान और बाबर की अनदेखी रिजवान और बाबर को जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान की पिछली दो सीरीज में भी बाहर रखा गया था। माना जा रहा है कि पीसीबी अगले

साल होने वाले टी20 विश्व कप को देखते हुए अपने शीर्ष क्रम में नए खिलाड़ियों को मौका दे रहा है। चयनकर्ताओं ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 1-4 से शिकस्त झेलनी वाली टीम में आठ बदलाव किए हैं। इन खिलाड़ियों को मिला मौका तेज गेंदबाजों शाहीन शाह अफरीदी,

जहानदान खान और अब्बास अफरीदी की जगह हसन, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम को टीम में शामिल किया गया है। सलामी बल्लेबाज साहिबजादा फरहान, सैम अयूब और फखर जमां की टीम में वापसी हुई है जबकि ऑलराउंडर फहीम अशरफ और हुसैन तलत को भी एक बार फिर टीम में शामिल किया गया है। पाकिस्तान की टीम इस प्रकार है सलमान अली आगा (कप्तान), शादाब खान, अब्बास अहमद, फहीम अशरफ, फखर जमां, हारिस राऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हुसैन तलत, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद वसीम, इरफान खान, नसीम शाह, साहिबजादा फरहान और सैम अयूब।

दिल्ली की उम्मीदों पर मुंबई ने फेरा पानी, प्लेऑफ में पहुंची; सूर्यकुमार के बाद सैंटनर-बुमराह चमके

मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल्स को 59 रनों से हरा दिया। इसी के साथ मुंबई आईपीएल 2025 के प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई। इससे पहले गुजरात टाइटंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और पंजाब किंग्स ने प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई किया था। बुधवार को वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए मैच में टॉस हारकर बल्लेबाजी करने उतरी मुंबई ने सूर्यकुमार यादव की अर्धशतकीय पारी के दम पर पांच विकेट खोकर 180 रन बनाए। जवाब में दिल्ली 18.2 ओवर में सिर्फ 121 रन ही बना पाई और ऑलआउट हो गई। मुंबई के लिए जसप्रीत बुमराह और



मिचेल सैंटनर ने तीन-तीन विकेट झटके जबकि ट्रेट बोल्ट, दीपक चाहर, विल जैक्स और कर्ण शर्मा ने एक-एक सफलता अपने नाम की। दिल्ली को मात देकर मुंबई ने प्लेऑफ के लिए सीधे क्वालिफाई कर लिया है। हालांकि, दोनों टीमों के ग्रुप चरण में अभी एक-एक मैच बचे हैं। 24 मई (शनिवार) को दिल्ली कैपिटल्स का

सामना पंजाब किंग्स से होगा जबकि 26 मई (सोमवार) को मुंबई इंडियंस की पंजाब किंग्स से भिड़त होगी। ये दोनों मुकाबले जयपुर में खेले जाएंगे। लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली को उसके बल्लेबाजों ने निराश किया। उनके लिए समीर रिजवी ने सर्वाधिक 39 रनों की पारी खेली। इसके अलावा सिर्फ तीन बल्लेबाज दहाई का आंकड़ा

छू पाए। इनमें केएल राहुल (11), विप्रज निगम (20) और आशुतोष शर्मा (18) शामिल हैं। मुंबई के खिलाफ मैच में टीम के नियमित कप्तान अक्षर पटेल तबीयत खराब होने की वजह से नहीं खेलने उतरे। उनकी जगह फाफ डुप्लेसिस ने दिल्ली का नेतृत्व किया। वह सिर्फ छह रन बना पाए। इसके अलावा अभिषेक पोरेल ने छह, ट्रिस्टन स्टुब्स ने दो, माधव तिवारी ने तीन, कुलदीप यादव ने सात रन बनाए। वहीं, मुस्तफिजुर रहमान खाता भी नहीं खोल पाए जबकि दुष्मंथा चमीरा आठ रन बनाकर नाबाद रहे।

कान में ऐश्वर्या ने सबको कहा नमस्ते, व्हाइट साड़ी और सिंदूर से दिखाई भारतीय संस्कृति



कान फिल्म फेस्टिवल हो और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय न हों, ऐसा भला कैसे हो सकता है? 78वें कान फिल्म फेस्टिवल में अदाकारा शिरकत करने पहुंची हैं। आज बुधवार को वे रेड कार्पेट पर उतरीं। इस बार ऐश व्हाइट साड़ी में रेड कार्पेट पर जलवा बिखेरती नजर आईं। उन्होंने सिंदूर के साथ अपना लुक कंप्लीट किया।

नमस्ते कहकर किया अभिवादन

ऐश्वर्या राय रेड कार्पेट पर व्हाइट साड़ी में कान के रेड कार्पेट पर पहुंचीं, जिस पर गोल्डन कलर के बॉर्डर से डिजाइन है। इस दौरान उन्होंने नमस्ते कहकर वहां उपस्थित लोगों का अभिवादन किया। ऐश्वर्या राय बच्चन साल 2002 में पहली बार कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई थीं।

पहली बार इस फिल्म के लिए कान फेस्टिवल में की शिरकत

ऐश्वर्या राय बच्चन साल 2002 में पहली बार फिल्म 'देवदास' के प्रीमियर के लिए कान फिल्म फेस्टिवल में शामिल हुई थीं। इसके बाद हर साल एक मेकअप ब्रॉन्ड के लिए वे इस फिल्म फेस्टिवल में शामिल होती हैं। ऐश्वर्या का लुक भी हर साल चर्चा में रहता है। इस बार उनका जुदा अंदाज देखने को मिला है।

इस लुक में ऐश्वर्या रॉयल क्वीन लग रही हैं। नेटिजन्स उनकी जमकर तारीफ कर रहे हैं। यूजर्स को उनका ट्रेडिशनल लुक काफी पसंद आ रहा है। एक यूजर ने लिखा, 'काफी वक्त बाद आपको साड़ी में देखा, बहुत प्यारी लग रही हैं आप'। एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मदर ऑफ कान फिल्म फेस्टिवल'। एक अन्य यूजर ने लिखा, 'आपका लुक इस बार दिल जीत ले गया'।

बच्चन परिवार की बहू ने जीता दिल

कान फिल्म फेस्टिवल में ऐश्वर्या राय के लुक का सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। आज बुधवार को उनका लुक जब सामने आया तो सभी ने दिल थाम लिया। बच्चन परिवार की बहू और लोकप्रिय अदाकारा ने साड़ी के साथ पारंपरिक गहनों से लुक पूरा किया।

भारत के मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम पर बनेगी फिल्म, धनुष निभाएंगे अहम किरदार



भारत के 11वें राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम पर एक बायोपिक बन रही है। इस फिल्म का निर्देशन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता निर्देशक ओम राउत करेंगे।

राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता सुपरस्टार धनुष इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएंगे।

कान में हुआ फिल्म का ऐलान

फिल्म का निर्माण अभिषेक अग्रवाल कर रहे हैं। साईविन क्वाड्रास ने इसका लेखन किया है। दिग्गज अभिनेता धनुष डॉ. कलाम की भूमिका निभा रहे हैं।

फिल्म के निर्माताओं ने कान फिल्म फेस्टिवल में इस फिल्म का ऐलान किया है। जब ओम राउत और धनुष फिल्म पर चर्चा करने के लिए मिले, तो उन्हें एहसास हुआ कि वे अपने ज़िंदगी की सबसे बड़ी फिल्म साथ में बना रहे हैं।

निर्देशक ओम राउत ने की तारीफ

राउत ने एक बयान में कहा 'सच्चे राजनेताओं की कमी वाले युग में, कलाम राजनीति और संकीर्णता से ऊपर खड़े थे। वह एक ऐसे व्यक्ति थे जो शिक्षा और स्वदेशी नवाचार की ताकत के लिए जाने जाते थे।

सोने से पहले चेहरे पर विटामिन-E कैप्सूल लगाने के साइंटिफिक फायदे जानिए, मिलेगी खूबसूरत और जवां त्वचा

बिगड़ी हुई लाइफस्टाइल का असर लोगों के शरीर के साथ-साथ चेहरे पर भी दिखाई देता है। खासकर, गर्मियों में स्किन से जुड़ी प्रोब्लेम्स सबसे ज्यादा होती हैं। जब हम रात को सोते हैं, तब हमारी त्वचा खुद को रिपेयर करती है। यही वो वक्त होता है जब थोड़ी सी केयर हमें चमकती और हेल्दी स्किन दे सकती है।

ऐसे में अगर आप चाहते हैं कि आपकी त्वचा सुबह उठते ही ग्लोइंग और सॉफ्ट नजर आए, तो विटामिन E कैप्सूल को अपनी नाइट स्किनकेयर में जरूर शामिल कर सकते हैं। विटामिन E एक नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट है, जो स्किन को हाइड्रेट करता है, एजिंग को धीमा करता है और दाग-धब्बों को हल्का



करने में मदद करता है। आइए जानें सोने से पहले चेहरे पर विटामिन E कैप्सूल कैसे लगाएं? जानिए 3 आसान तरीके

विटामिन E कैप्सूल को कैसे करें इस्तेमाल
ब्यूटी एक्सपर्ट्स के अनुसार, एक विटामिन E कैप्सूल अपने हाथ में लें।

उसमें पिन की मदद से छेद करें और उसका ऑयल निकाल लें।
चेहरे को सबसे पहले फेसवॉश से धोकर अच्छे से सुखा लें।
अब उंगलियों से ऑयल को हल्के हाथों से पूरे चेहरे और गर्दन पर लगाएं
इससो 2 मिनट तक मसाज करें और इसी तरह से रातभर छोड़ दें।
इसे पूरी रात चेहरे पर लगा रहने दें और सुबह उठकर हल्के गुनगुने पानी से धो लें।
यह तरीका ड्राई स्किन वालों के लिए सबसे ज्यादा फायदेमंद है।
मॉइस्चराइजर में मिलाकर लगाएं
अपनी रोज की नाइट क्रीम या मॉइस्चराइजर लें

उसमें 1 विटामिन ई कैप्सूल का तेल मिलाएं।
इसके बाद अच्छी तरह मिक्स करके चेहरे पर लगा लें।
इससे स्किन को डबल फायदा मिलेगा।
यह तरीका नॉर्मल से लेकर सेंसिटिव स्किन वालों के लिए सही है।
ऐलोवेरा जेल के साथ मिलाएं
1 चम्मच ऐलोवेरा जेल लें।
उसमें 1 विटामिन ई कैप्सूल का तेल मिलाएं।
दोनों को अच्छी तरह मिक्स करें और चेहरे पर लगाएं।
5 मिनट तक मसाज करें और फिर इसे छोड़ दें।
यह स्किन की रेडनेस कम करता है और नेचुरल ग्लो देता है।

जिसके लिए 14.5 लाख करोड़ खर्चने को तैयार ट्रंप; किस खतरे से सुरक्षा की तैयारी?



“ चुनाव प्रचार के दौरान मैंने अमेरिकी लोगों से वादा किया था कि मैं अपने देश को विदेशी मिसाइल हमले के खतरे से बचाने के लिए अत्याधुनिक मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाऊंगा।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसी साल मार्च में अमेरिकी संसद में दिए अपने भाषण में इस्राइल के आयरन डोम सुरक्षा कवच की तर्ज पर ही अपने देश में एक गोल्डन डोम बनाने का प्रस्ताव रखा था। मंगलवार को उन्होंने इस सिस्टम की तैनाती को लेकर मंजूरी भी दे दी। ट्रंप ने कहा, 'हम गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड के बारे में ऐतिहासिक घोषणा कर रहे हैं। यह कुछ ऐसा है जो हम चाहते हैं। रोनाल्ड रीगन (40वें अमेरिकी राष्ट्रपति) इसे कई साल पहले ही चाहते थे, लेकिन उनके पास तकनीक नहीं थी।' यह योजना अमेरिका की पहली ऐसी प्रणाली होगी जिसमें अंतरिक्ष में हथियार तैनात किए जाएंगे। ऐसे में यह जानना अहम है कि आखिर ट्रंप ने जिस गोल्डन डोम के निर्माण को मंजूरी दी है, वह है क्या? अमेरिका को अब इसकी जरूरत क्यों है? उसे किस तरह के हमलों और

हथियारों से खतरा महसूस हुआ है? इसके अलावा अमेरिका का यह गोल्डन डोम इस्राइल के आयरन डोम से कितना अलग होगा? आइये जानते हैं... गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस शील्ड से जुड़ी घोषणा को लेकर व्हाइट हाउस की तरफ से जारी एक वीडियो संदेश में ट्रंप ने कहा, 'यह कुछ ऐसा है जो हमारे पास होगा। हम इसे उच्चतम स्तर पर रखने जा रहे हैं।' अमेरिका को अचानक क्यों याद आई इस्राइल जैसी रक्षा व्यवस्था बनाने की याद? ऐसा नहीं है कि अमेरिका के पास अब तक किसी भी तरह के हमले के लिए कोई रक्षा कवच नहीं है। अमेरिका ने अपने आसपास पूर्वी तट और अटलांटिक महासागर में किसी भी तरह के खतरे से निपटने के लिए यूएस फ्लीट फोर्स कमान की तैनाती की है। वहीं, जमीनी क्षेत्रों में अमेरिका ने दूसरे देशों से लगती अपनी सीमाओं ही नहीं, बल्कि दुनियाभर में अलग-अलग

जगहों पर सैन्य, नौसैन्य और वायुसेना के लिए बेस कैंप भी बनाए हैं। इससे अमेरिकी सेना पूरी दुनिया में किसी भी क्षेत्र में कुछ घंटों के अंदर ही हमले करने और किसी खतरे से खुद का बचाव करने में सक्षम है। हालांकि, यह टुकड़ियां पूरा हवाई क्षेत्र कवर नहीं करतीं। यानी कई ऐसे क्षेत्र भी हैं, जो कि अमेरिकी सेना, वायुसेना और नौसेना के लिए ब्लाइंड स्पॉट हैं। ऐसे में दुश्मन इन क्षेत्रों की पहचान कर के या आसानी से रडार की पकड़ में न आने वाले हथियारों के जरिए उसे निशाना बना सकता है। अमेरिका के पास फिलहाल ऐसी कोई सुरक्षा प्रणाली नहीं है, जिसके जरिए वह आधुनिक समय की हाइपरसोनिक मिसाइलों, ड्रोन हमलों की बाढ़ का सामना कर सके। अमेरिका के पास फिलहाल हवाई हमलों से रक्षा के लिए कुछ मिसाइल डिफेंस सिस्टम जरूर हैं। इनमें पेट्रियट

मिसाइल डिफेंस सिस्टम, नाइकी हरक्यूलीज सिस्टम और टर्मिनल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस (THAAD) सिस्टम प्रमुख हैं। इसके अलावा अमेरिका ने कुछ बैलिस्टिक मिसाइलों को भी अपनी सुरक्षा के लिए देश और बाहर समुद्री क्षेत्रों में तैनात किया है। हालांकि, यह पूरी व्यवस्था अब तक काफी बिखरी हुई मानी जाती है। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि तकनीकी क्षमता होने के बावजूद अगर अमेरिका पर हमलों की बाढ़ आती है तो यह सुरक्षा प्रणाली टूट सकती है। ऐसे में अमेरिका को सुरक्षा कवच के तौर पर एक केंद्रीकृत प्रणाली की जरूरत है। अमेरिका की मौजूदा हवाई सुरक्षा व्यवस्थाओं को इस्राइल के आयरन डोम सिस्टम की टक्कर का नहीं माना जाता। दरअसल, आयरन डोम सिस्टम एक एकीकृत रक्षा प्रणाली है, जो हवाई हमलों को एक साथ रोकने में सक्षम है। यह सिस्टम एक साथ पूरे इस्राइल की सुरक्षा के लिए लगाया गया है। इसकी वजह से ही हमला और हिजबुल्ला की तरफ से किए गए बड़े मिसाइल और ड्रोन हमलों को इस्राइल नाकाम कर चुका है। डोनाल्ड ट्रंप ने संसद में दिए अपने भाषण में अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन के नाम का जिक्र किया।

सिंगापुर की सरकार में भारतवंशियों का दबदबा, पीएम लॉरेंस वोंग ने इन नेताओं को सौंपी जिम्मेदारी



सिंगापुर की सरकार में भारतवंशियों का दबदबा है। देश के नए प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने बुधवार को नए मंत्रिमंडल का एलान किया है। 17 सदस्यीय मंत्रिमंडल में भारतीय मूल के छह नेताओं को जगह दी गई है। इन नेताओं को विदेश, व्यापार, गृह समेत अहम विभागों का जिम्मा सौंपा गया है। देश में तीन मई को हुए आम चुनावों में लॉरेंस वोंग की पीपुल्स एक्शन पार्टी (पीएपी) ने भारी जीत हासिल की। प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग ने नए मंत्रिमंडल का एलान किया। इसमें तीन समन्वय मंत्री शामिल हैं। वहीं गान किम योंग को उपप्रधानमंत्री बनाया गया है। मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री कार्यालय और 16 मंत्रालयों में 15 मंत्री और दो कार्यवाहक मंत्री भी शामिल किए गए हैं। प्रधानमंत्री वोंग ने भारतीय मूल के षण्मुगम को गृह मंत्री पद पर बरकरार रखा है। वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए समन्वय मंत्री का काम भी देखेंगे। जबकि वे कानून विभाग छोड़ देंगे। षण्मुगम अभी तक गृह मंत्रालय के साथ कानून विभाग भी देख रहे थे। इसके अलावा विवियन बालाकृष्णन विदेश मंत्री बने रहेंगे। जबकि इंद्राणी राजा प्रधानमंत्री कार्यालय में मंत्री होंगी। भारतीय मूल के मुरली पिल्लई को वरिष्ठ राज्य मंत्री बनाया गया है। वे कानून और परिवहन विभाग के मंत्री होंगे। इसके साथ ही जनिल पुथुचेरी को शिक्षा और पर्यावरण राज्य मंत्री, पीएपी के नए सदस्य और भारतीय मूल के दिनेश वासु दाश वरिष्ठ संसदीय सचिव नियुक्त किए गए हैं। वे दक्षिण पूर्व जिले के मेयर भी होंगे। वोंग ने कहा कि मैंने सिंगापुर के लिए सबसे मजबूत टीम बनाने की पूरी कोशिश की है। वोंग ने वित्त विभाग अपने पास ही रखा है।

नवी मुंबई पुलिस के सब-इंस्पेक्टर पर महिला कांस्टेबल के साथ बलात्कार और 5 साल से अधिक समय तक जाति-आधारित उत्पीड़न करने का मामला दर्ज

मुंबई: नवी मुंबई के एक पुलिस सब-इंस्पेक्टर (पीएसआई) पर एक महिला कांस्टेबल के साथ कथित तौर पर बलात्कार करने और पांच साल की अवधि तक उसे जाति-आधारित दुर्व्यवहार का शिकार बनाने का मामला दर्ज किया गया है। आरोपी, जो वर्तमान में वाशी पुलिस स्टेशन में तैनात है, ने कथित तौर पर एक रोमांटिक रिश्ते के बहाने कांस्टेबल का शोषण किया, उसकी निजी तस्वीरें लीक करने की धमकी दी और उससे पैसे ऐंठे। मामले के बारे में पनवेल तालुका पुलिस के अनुसार,

आरोपी ने पहली बार महिला कांस्टेबल से 2020 में मुलाकात की थी, जब वह तलोजा पुलिस स्टेशन में तैनात था। उसका विश्वास जीतने के बाद, उसने कथित तौर पर उसे मार्च 2020 में महालक्ष्मी नगर, नेरे, पनवेल में एक किराए के कमरे में चाय पर बुलाया। वहाँ, उसने कथित तौर पर उसे नशीला पदार्थ दिया और बेहोशी की हालत में उसका यौन उत्पीड़न किया। उसने पीड़िता की अर्ध-नग्न तस्वीरें भी लीं और बाद में उन्हें उसे चुप कराने के लिए डराने-धमकाने के लिए इस्तेमाल



किया। पनवेल तालुका पुलिस स्टेशन के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, 'शिकायतकर्ता ने दावा किया है कि पीएसआई ने अप्रैल 2020 से अप्रैल 2025 के बीच पनवेल के एक घर

और खंडा कॉलोनी के एक लॉज सहित विभिन्न स्थानों पर उसका यौन शोषण करना जारी रखा। इस अवधि के दौरान, आरोपी ने कथित तौर पर शादी का वादा किया, लेकिन

कभी पूरा नहीं किया। इसके बजाय, उसने कार खरीदने के लिए 5 लाख रुपये की मांग की और मना करने पर उसके बेटे को उसकी अश्लील तस्वीरें दिखाने की धमकी दी। पीड़िता ने आखिरकार उसे 2 लाख रुपये ऑनलाइन और 3 लाख रुपये नकद दिए। जब महिला कांस्टेबल ने पीएसआई के अपनी पहली पत्नी से तलाक के बाद शादी पर जोर दिया, तो उसने कथित तौर पर उसे अपमानित करने और अस्वीकार करने के लिए जाति-आधारित गालियों का इस्तेमाल किया। अपनी

मां को दुर्व्यवहार के बारे में बताने पर, शिकायतकर्ता का दावा है कि उसे भी जातिवादी मौखिक दुर्व्यवहार और अपमान का सामना करना पड़ा। शिकायत के बाद, पनवेल तालुका पुलिस ने पीएसआई और उसकी मां के खिलाफ बलात्कार, आपराधिक धमकी, धोखाधड़ी और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों से संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की जांच अभी चल रही है।

कल्याण में 4 मंजिला इमारत का स्लैब ढहा, 6 की मौत

ठाणे: महाराष्ट्र के कल्याण में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसा हो गया। यहां चांदीनगर थाना क्षेत्र के मंगलराघो नगर में स्थित सप्तश्रृंगी नामक चार मंजिला आवासीय इमारत की दूसरी मंजिल का स्लैब अचानक गिर गया। यह स्लैब सीधा नीचे तक धंस गया, जिससे इमारत के निचले मंजिलों में रह रहे लोग भी चपेट में आ गए। हादसे में अब तक 6 लोगों की मौत होने की जानकारी सामने आई है, जिनमें 3 महिलाएं और डेढ़ साल की बच्ची भी शामिल हैं। 3 अन्य घायल लोगों को मलबे से बाहर निकाला गया है और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है। अनुमान है कि करीब 10 लोग अब भी मलबे के नीचे दबे हुए हैं। उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने दिए निर्देश इस घटना को लेकर उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने भी



निर्देश दिया है कि मलबे में फंसे लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए और इमारत में रहने वाले अन्य लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया जाए। उन्होंने दुर्घटना में मारे गए नागरिकों के परिजनों को जिला आपदा राहत कोष से सहायता प्रदान करने

को कहा। बारिश से राहत कार्यों में बाधा आने की आशंका बता दें कि घटना की सूचना जिला आपदा प्रबंधन सेल को दोपहर 3 बजे के दौरान मिली, जिसके बाद थाने की डिजास्टर रिसपॉन्स फोर्स ने त्वरित कार्रवाई करते हुए राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया था। मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी दी है, जिससे राहत कार्यों में बाधा आने की आशंका है। प्रमिला साहू (58), नामस्वी शेलार (1.5), सुनीता साहू (37), सुजाता पाडी (32), सुशीला गुजर (78), व्यंकट चव्हाण (42)। घायलों के नाम: अरुणा रोहिदास गिरणारायन (48), शरवील श्रीकांत शेलार (4), विनायक मनोज पाधी (45), यश क्षीरसागर (13), निखिल खरात (27), श्रद्धा साहू (14)।

15000 के चीनी ड्रोन को मारने के लिए 15 लाख की मिसाइलें क्यों इस्तेमाल की कांग्रेस नेता वडेटीवार का सवाल

महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता विजय वडेटीवार ने चीन के ड्रोन को खत्म करने के लिए भारत की तरफ से इस्तेमाल किए गए हथियारों पर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान 15,000 रुपये की लागत वाले पाकिस्तान की ओर से दागे गए चीनी ड्रोन को रोकने के लिए 15 लाख रुपये की लागत वाली मिसाइलों का इस्तेमाल क्यों किया गया? नागपुर में पत्रकारों से बात करते हुए पूर्व राज्य मंत्री ने कहा कि मैं जानना चाहता हूं कि क्या संघर्ष में हुए नुकसान के बारे में सरकार से पूछना गलत है? कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान के खिलाफ 'छुटपुट' (छोटा) युद्ध बताए जाने के बारे में पूछे गए सवाल पर वडेटीवार ने कहा कि संघर्ष में देश को हुए नुकसान और सैनिकों के हताहत होने के बारे में सरकार से सवाल पूछना गलत नहीं है। क्या हमने पाकिस्तान के खिलाफ सैन्य अभियान के दौरान राफेल जेट खो दिए? चीन के ड्रोन को खत्म करने के लिए 15 लाख की मिसाइलें क्यों इस्तेमाल की?



कृषि लोन को लेकर किसानों के CIBIL स्कोर न मांगे बैंक, वरना लेंगे एक्शन- CM फडणवीस का आदेश

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्राइवेट बैंकों के वरिष्ठ अफसरों को कृषि लोन के लिए आवेदन करने वाले किसानों से क्रेडिट रेटिंग (CIBIL) स्कोर मांगने को लेकर कड़ी फटकार लगाई है। सीएम ने अफसरों को चेतावनी दी कि अगर उनके बैंक CIBIL स्कोर की मांग जारी रखते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, उनसे इस मुद्दे को गंभीरता से लेने और तत्काल समाधान निकालने को आदेश दिया। सहाद्री गेस्ट हाउस में आयोजित

167वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की बैठक के दौरान सीएम फडणवीस की अगुवाई में हुई 167वीं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक के दौरान मुद्दा सामने आया, जहां वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 44.76 लाख करोड़ रुपये के लोन वितरण योजना को मंजूरी दी गई। चर्चा के दौरान बताया गया कि निजी बैंक सिबिल स्कोर मांग रहे हैं। गंभीर मसला, बैंक समझे जिम्मेदारी: C M फडणवीस सिबिल स्कोर, क्रेडिट इंफार्मेशन ब्यूरो का एक



क्रेडिट पात्रता मैकेनिज्म है, जिसका इस्तेमाल वित्तीय संस्थानों की ओर से लोन आवेदनों का आकलन करने के लिए किया जाता है। इसमें कर्ज चुकाने की क्षमता पर भी ध्यान केंद्रित

किया जाता है। फडणवीस ने कहा, "अगर किसानों को कृषि लोन नहीं मिलता है, तो इसका अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल असर पड़ता है और किसानों की खुदकुशी की दर बढ़ती है। हमने

बैंकों को बार-बार यह निर्देश दिया है कि वे सिबिल (स्कोर) की मांग न करें, लेकिन वे ऐसा अभी भी कर रहे हैं। इसे आज (सोमवार) की बैठक में ही हल किया जाना चाहिए। पहले भी ऐसे कई बैंकों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है। यह एक गंभीर मुद्दा है जिसे बैंकों को इसे जिम्मेदारी से संभालना चाहिए।" राज्य में खेती की उपेक्षा स्वीकार्य नहीं: CM फडणवीस बैंकों पर सख्ती करते हुए फडणवीस ने आगाह करते हुए कहा, "भारतीय रिजर्व बैंक ने भी

कृषि लोन के संबंध में साफ कर दिया है कि यदि कोई बैंक सिबिल स्कोर पर जोर देती है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।" साथ ही मुख्यमंत्री ने सरकारी बैंकों को इस साल के लोन वितरण लक्ष्यों को पूरा करने और कृषि लोन कवरेज का विस्तार करने के लिए विशेष प्रयास करने के निर्देश दिए। इस बैठक के दौरान, वित्त वर्ष 2025-26 के लिए महाराष्ट्र के लिए 44.76 लाख करोड़ रुपये की लोन स्कीम को मंजूरी दी गई।